(a) whether Government have made any survey with regard to people living in the Jhonpur Patti which is a slum area in the Bombay city on the vacant Railway land lying on both sides of the Railway track;

(b) whether it is a fact that the Railways have not allowed development of this slum area where people of worker sections are living for the last fifty years;

(c) whether Government are contemplating to take over this land from the Railway for allotment to people already living in Jhonpur Patti which falls on both sides of the Railway track; and

(d) if so, what are the details in this regard; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों पर बकाया धनराशि

3036. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) ऐसे वर्तमान और भूतपूर्व मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन पर सरकारी आवास के किराये की धनराशि बकाया है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है और की जा रही है तथा उसके क्या परिणाम हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आदिवासियों के लिए कृषि योजनाएं

3037. **श्री अजीत जोगी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि आदिवासियों की कृषि आय कम होने का एक प्रमुख कारण उनकी कृषि भूमि का समतल न होना है,

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उनकी भूमि के समतलीकरण के लिए भूमि संरक्षण स्कीम के अधीन वर्तमान ऋण और अनुदान की व्यवस्था के स्थान पर, जिसका आदिवासी लाभ नहीं उठा पाते हैं और यदि उनमें से कोई इसका लाभ उठाता भी है तो उसे अत्याधिका ऋण की वसूली करके उसका शोषण किया जाता है, शत-प्रतिशत अनुदान उन्मुखी कोई योजना आरम्भ करेगी ताकि वे अपनी कृषि भूमि को समतल बना सकें और अपनी आय के अत्यल्प साधनों का उचित दोहन कर सकें ; और

(ग) क्या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अधीन विभिन्न रोजगार उन्मुखी स्कीमें के इस प्रकार संशोधित किए जाने का विचार है कि उनके अधीन भी आदिवासियों की कृषि भूमि के समतलीकरण का कार्य आरम्भ किया जा सके ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) जी, हां । कृषि भूमि की असमानता, कम पैदावार के कारणों में से एक है, जिसके फलस्वरूप आदिवासियों की आमदनी कम होती है ।

(ख) ऊबड़-खाबड़ भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत एक घटक भू-समतलन है । आदिवासियों की कृषि-भूमि के विकास के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा राज सहायता की विभिन्न पद्धितियां अपनायी जा रही हैं । तथापि, केन्द्रीय सरकार ने झूम खेती के

नियंत्रण के लिए 1987–88 में एक योजना चलाई है। इस योजना के तहत प्रमुख रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और त्रिपुरा राज्यों के आदिवासियों के लाभ के लिए राज्य योजना को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। भू-समतल इस योजना का एक अंग है.

(ग) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में व्यक्तिगत लाभानुभोगी उन्मुखी कार्यों जैसे अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित भूमि विकास के लिए पहले ही प्रावधान है।

Complaints against Sarva Priya Co-operative House Building Society

3038. SHRIMATI MANORAMA PANDEY: Will the Miniter of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to various newspaper reports in national media during the last 6 months about the clandestine functioning of Sarva Priya Cooperative Housing Building Society, New Delhi and its promoters;

(b) whether it is a fact that some Members of Parliament have also written to Government for a thorough probe into the affairs of this society;

(c) if so, what are the allegations made against the promoters of this society and what steps have been taken against them; and

(d) whether it is also a fact that a large number of Members of the society and its occupants have also made number of complaints about the society and if so, what action has been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Application of fertilisers control order

3039. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Fertilisers Control Order, 1985 is applicable only to imported fertilisers or both imported as well as indigenous;

(b) what are the reasons for violating the provisions of FCO and discreminating between Public Sector and private enterprises by giving exemption only to Food Corporation of India; and

(c) whether Government are proposing any suitable amendment in the existing FCO 1985 and; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) Fertiliser (Control) Order, 1985 is applicable to both imported as well as indigenous fertilisers.

(b) In accordance with the provisions of clause 23(3) of Fertiliser (Control) Order, 1985, the Food Corporation of India was exempted recently from the operation of the provisions of paragraphs (a) & (b) of sub-clause (1) of clause 23 of Fertiliser (Control) Order, 1985 in respect of imported fertilisers handled by them on behalf of the Central Government. This does not constitute a violation of the provisions of the FCO.

(c) No, Sir.

Loan and grant to back-ward villages under town panchayats in Tamil Nadu

3040. SHRI N. RAJANGAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the most backward villages under Town Panchayats in Tamil Nadu have been deprived of being the beneficiaries of